

Mr. Deputy Chairman in the. Chair] 1. Reports and Accounts (1980-81 and 1981-82) of the Shellac Export Promotion Council, Calcutta and. related papers.

H. Textiles Committee (Amendment) Rules, 1983

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. A. SANGMA): Sir, I beg to lay the Table:—

*

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) Twenty-fourth Annual Report and Accounts of the Shellac Export Promotion Council, Calcutta, for the year 1980-81 and the Audit Report on the Accounts together with Review by Government on the working of the Council.

(ii) Twenty-fifth Annual Report and Accounts of the She-port Promotion Council, Calc for the year '1981-82 and the Audit Report on the Accounts together with Review by Government on the working

reasons
for the delay in laying the papers mentioned at (i) and (ii) above.

in Library. See No. LT-84 for (i) to (ii)

II. A copy (in English and Hindi) Of the Ministry of Commerce (Department of Textiles) Notifications

S.R. No. 850, dated the 2nd November, 1983. publishing the Textiles Committee (Amendment) Rules, 1983, under sub-section (3) of section 22 of the Textiles Committee Act, 1963. [Placed in Library. See No. LT-794V84]

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Asiatic Society Bill, 1984

SECRETARY-GENERAL; Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok

Sabha signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of Rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 19th March, 1984 agreed without any amendment to the Asiatic Society Bill, 1984, -which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 51 h March, 1984.

REFERENCE TO THE BANNING OF THE ALL INDIA SIKH STUDENTS' FEDERATION.

श्री लाडली मोहन निगम (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मुझे एक निवेदन करना है। आज मैं एक व्यवस्था का प्रश्न और साथ ही साथ संसदीय नैतिकता का प्रश्न आज के सदन रखना चाहता हूँ और उस पर आपसे रोशनी चाहता हूँ। मैं किसी की विषय पर शक नहीं करता। आज एक खबर छपी है कि रात को बहुत देर कोई अधिसूचना के जरिए सिखों के उग्रवादी विद्यार्थी संगठन या उसके श्रद्धालुओं को बैन किया गया। जो उनकी हुरकते है उन से किसी को लेना-देना नहीं है, उन को इस कठोर करने हैं, मैं भर्त्सना भी करता हूँ। मैं निरंक यह जानना चाहता हूँ कि जब संसद बैठती हो तो क्या वह सोचि-वपूर्ण नहीं भा कि संसद को सूचना दी जा सकती या आज जो भी सम्बन्धित गृह मंत्री जो जो वह सदन को सूचित कर देते उस अधिसूचना के बारे में वितरण इस के कि सूचना रात को जारी करके अखबार में छपने के बाद पता चला। यह नैतिकता का प्रश्न है। हो सकता है कि उन के अधिकारक्षेत्र में हो, जो कि नहीं होना चाहिए जब संसद बैठती हो, 'आडिनेस नहीं' निकाल सकते तो एक्जीक्यूटिव आर्डर पर इस तरह अमलदरामद नहीं होना चाहिए।